

मुकदमों का विवरण

सी. अनिल चंद्रन बनाम

एम. के. राघवन और अन्य (2012 की सिविल अपील संख्या 8915) 30 अक्टूबर, 2023

[हिमा कोहली और राजेश बिंदल, जे. जे.]

हेडनोट्स

विचार के लिए विषय:अपीलार्थी मुख्य अभियंता, सिंचाई और प्रशासन द्वारा पारित दिनांक 14.03.2005 के आदेश से व्यथित था, जिसके अनुसार निजी उत्तरदाता संख्या 1 से 4,7 और 8 को पिछली तारीख से वरिष्ठता दी गई थी।

सेवा विधि -वर्ष **2004** में निजी प्रत्यर्थियों के नेतृत्व में दायर रिट याचिका में, उच्च न्यायालय ने उनकी श्रेणी के लिए आरक्षित कोटे में पदोन्नति के उनके मामलों पर विचार करने का निर्देश दिया-इस मामले पर मुख्य अभियंता द्वारा विचार किया गया और दिनांक **2** के आदेश के माध्यम से इसका निपटारा किया गया और अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद, सहायक अभियंता के रूप में पदोन्नति **1** से दी गई-इसके बाद अपीलार्थी के नेतृत्व में एक अन्य रिट याचिका में, दिनांक **2** के आदेश को उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा दरकिनार कर दिया गया, हालांकि रिट अपील में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कहा कि निजी प्रत्यर्थियों की पदोन्नति का एंटी-डेटिंग अपीलार्थी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं कर रहा था-इसलिए, दिनांक **1** का आदेश अपीलार्थी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा था।

आयोजित किया गया:हाथ में मामले में, वरिष्ठता सूची को निजी उत्तरदाताओं द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी-उन्होंने केवल सहायक अभियंता के रूप में अपनी पदोन्नति की तारीखों में सुधार के लिए अभ्यावेदन किया था, जिसे राज्य द्वारा 14.03.2005 पर स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लिया गया था-तत्काल अपील में हस्तक्षेप के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया क्योंकि अपीलकर्ता सहायक अभियंता के पद से 145 तक पदोन्नति के उद्देश्य से यह प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं है।

सी. अनिल चंद्रन बनाम एम. के. राघवन और अन्य 146 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

सहायक कार्यपालक अभियंता की पदोन्नति की तारीख से पहले निजी उत्तरदाताओं के लिए अलग कोटा निर्धारित किए जाने की संभावना थी क्योंकि स्नातक अभियंताओं और डिप्लोमा धारकों की श्रेणियों के लिए अगले उच्च पद पर पदोन्नति के लिए अलग कोटा निर्धारित किया

गया था-2010 के नियमों को अपीलार्थी द्वारा 2017 के आई. ए. संख्या 02 के साथ रिकॉर्ड में रखा गया है, जिसके संदर्भ में डिग्री धारकों और डिप्लोमा धारकों के लिए 8 के अनुपात में अलग कोटा निर्धारित किया गया है:2 – अपीलार्थी निर्विवाद रूप से स्नातक अभियंता की श्रेणी में आता है, जबकि निजी उत्तरदाता डिप्लोमा धारकों की श्रेणी में आते हैं-दोनों अलग-अलग कोटा के साथ अलग-अलग धाराएँ हैं।[पैरा 19,20]

नगरों और अन्य संदर्भों की सूची

विनोद प्रसाद रतुरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, 2021 आई. एन. एस. सी 157 – संदर्भित किया गया।

आर. एम. रामूलल बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य। (1989) 1 एससीसी 285:[1988] 3 पूरक।एस. सी. आर. 1009-लागू नहीं होता।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं
सिविल अपीलीय अधिकारिता 2012 की सिविल अपील No.8915।

2010 के डब्ल्यू. ए. No.1563 में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

डॉ. के. पी. कैलासनाथ पिल्लै, वरिष्ठ अधिवक्ता, ए. वेनायगम बालन, गौरव पाल, किरीटकुमार गोविंदलाल सेठ, आश्रय बेहुरा, दीपक पाराशर, प्रखर सिंह, अधिवक्ता।
अपीलार्थी के लिए।

जयंत मुथ राज, सीनियर एड., पी. ए. नूर मुहम्मद, निशे राजन शोंकर, श्रीमती अनु के जॉय, आलिम अनवर, अब्राहम मैथ्यू, एड.प्रत्यर्थीगणों के लिए।

सर्वोच्च निर्णय के निर्णय का निर्णय/आदेश

राजेश बिंदल, जे।

1. वर्तमान अपील में चुनौती उच्च न्यायालय 2 की खंड पीठ द्वारा पारित एक रिट अपील 1 के आदेश को दी गई है, जिसके द्वारा 2005 के डब्ल्यू. पी. संख्या 36424 में पारित विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को रद्द कर दिया गया था।

2. अपीलार्थी के नेतृत्व में डब्ल्यू. पी. एफ. आई. में चुनौती मुख्य अभियंता, सिंचाई और प्रशासन, तिरुवनंतपुरम द्वारा पारित दिनांक 14.03.2005 के आदेश को दी गई थी, जिसके अनुसार निजी-प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4,7 और 8 को पिछली तारीख से वरिष्ठता दी गई थी।

3. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि अपीलार्थी को जी. ओ. के माध्यम से सिंचाई विभाग में पर्यवेक्षक ग्रेड-III के रूप में नियुक्त किया गया था। (आरटी.) नहीं. अनुकंपा के आधार पर को-ऑप दिनांकित 16.06.1989। चूंकि अपीलार्थी एक इंजीनियरिंग स्नातक था, इसलिए उसने सहायक अभियंता (मैकेनिकल) के रूप में नियुक्ति के लिए सरकार का प्रतिनिधित्व किया। उनका प्रतिनिधित्व अस्वीकार कर दिया गया था। 1991 के ओ. पी. सं. 7647 के नेतृत्व में उनके प्रतिनिधित्व की अस्वीकृति के आदेश को एक और प्रार्थना के साथ अपास्त करते हुए का अनुरोध किया गया था कि उन्हें पर्यवेक्षक ग्रेड-III के रूप में नियुक्त किए जाने की तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ सहायक अभियंता के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। आई. डी. 1 दिनांकित निर्णय के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने उसमें प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे अपीलार्थी को उस पद पर नियुक्त होने की तारीख से पर्यवेक्षक ग्रेड-III के बजाय सहायक अभियंता के रूप में नियुक्त करें। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के उपरोक्त निर्णय को राज्य द्वारा एक अंतर-न्यायालय अपील 3 द्वारा चुनौती दी गई थी। इसे 03.09.1994 पर निपटाया गया था, जिसमें सरकार को मौजूदा रिक्ति या अगली उत्पन्न होने वाली रिक्ति पर अपीलार्थी को सहायक अभियंता के रूप में नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने आगे निर्देश दिया कि अपीलार्थी को उनकी नियुक्ति की तारीख से सहायक अभियंता के संवर्ग में वरिष्ठता दी जानी चाहिए। उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में

1 2010 की रिट अपील संख्या 1563, केरल के उच्च न्यायालय पर निर्णय लिया गया

3 1992 147 की लिखित अपील सं. 1013

सी. अनिल चंद्रन बनाम एम. के. राघवन और अन्य [राजेश बिंदल, जे.] 148

न्यायालय, अपीलार्थी को जी. ओ. के माध्यम से सिंचाई विभाग में सहायक अभियंता (यांत्रिक) के रूप में नियुक्त किया गया था। (एमएस) नं. 31/95 सहकारी दिनांक 01.03.1995। 4. निजी-उत्तरदाता जो पर्यवेक्षक ग्रेड-I के रूप में सेवा में शामिल हुए और डिप्लोमा की योग्यता प्राप्त कर रहे थे, उन्हें 15.03.1995 और 18.03.1995 से प्रभावी होने के साथ सहायक अभियंता (मैकेनिकल) के रूप में पदोन्नत किया गया। सहायक अभियंता के पद से अगली उच्च पदोन्नति सहायक कार्यकारी अभियंता की है, जिसे 2010 के नियमों के अनुसार निर्धारित किया गया है। 4 5. यह आगे तर्क दिया गया कि मुख्य अभियंता 5 ने दिनांक 26.04.1996 के आदेश के माध्यम से, 01.03.1996 पर सहायक अभियंताओं (यांत्रिक) की पहली अनंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की। इसे सभी संबंधितों को प्रसारित करने का निर्देश दिया गया था और उन्हें 15 दिनों के भीतर आपत्तियों को दर्ज करने की स्वतंत्रता दी गई थी। वरिष्ठता सूची में, अपीलार्थी के नाम का उल्लेख क्रम संख्या 35 पर किया गया है, जबकि निजी-प्रत्यर्थी संख्या 4 से 8 का नाम क्रम संख्या 37 से 41 पर है। सहायक अभियंता (यांत्रिक) के रूप में अपीलार्थी के शामिल होने की तारीख 01.03.1995 के रूप में दिखाई गई है, जबकि निजी-उत्तरदाता संख्या 4 से 8 को क्रमशः

18.03.1995, 15.03.1995, 15.03.1995, 15.03.1995 और 15.03.1995 के रूप में दिखाया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 3 को वरिष्ठता सूची में नहीं दिखाया गया था। निजी उत्तरदाताओं ने उपरोक्त अस्थायी वरिष्ठता सूची पर कोई आपत्ति नहीं जताई। दिनांक 18.10.1997 के आदेश के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 2 ने 01.09.1997 पर सहायक अभियंताओं (मैकेनिकल) की एक और अनंतिम वरिष्ठता सूची प्रसारित की। नियुक्त व्यक्तियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विचार करने के बाद, प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा 01.04.1990 से 31.12.1998 तक की अवधि के लिए 22.11.2001 के आदेश के माध्यम से सहायक अभियंताओं (मैकेनिकल) की कुल वरिष्ठता सूची प्रसारित की गई थी। संचार में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि इस संबंध में अवधि के लिए प्रकाशित सभी पिछली वरिष्ठता सूचियों को हटा दिया गया था। उपरोक्त वरिष्ठता सूची श्रेणीवार तैयार की गई थी, जिसमें ग्रेजुएट इंजीनियर, डिप्लोमा धारक और प्रमाण पत्र धारक शामिल थे। यही कारण था कि अगली उच्च पदोन्नति के लिए, अलग-अलग फीडर कैडरों के लिए कोटा थे। अपीलार्थी को स्नातक इंजीनियरों की श्रेणी में क्रम संख्या 37 पर दिखाया गया था और उनकी पदोन्नति की तारीख को 01.03.1995 के रूप में दिखाया गया था। उत्तरदाता संख्या 1 से 4 को डिप्लोमा धारकों की सूची में क्रम संख्या 9 से 12 पर उनके साथ दिखाया गया था।

4 केरल सिंचाई इंजीनियरिंग सेवा विशेष नियम, 2010 5 मुख्य अभियंता, सिंचाई और प्रशासन, तिरुवनंतपुरम

/

[2023] 14 एस सी आर।

पदोन्नति की तिथि 15.03.1995 के रूप में। निजी उत्तरदाताओं को उपरोक्त वरिष्ठता सूची से कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि उनके द्वारा इसे कभी चुनौती नहीं दी गई थी।

6. सहायक कार्यकारी अभियंता के रूप में आगे की पदोन्नति के लिए तीन अलग-अलग श्रेणियों जैसे स्नातक अभियंता, डिप्लोमा धारक और प्रमाण पत्र धारक से आने वाले सहायक अभियंताओं के मामलों पर विचार किया जाना था। मुख्य अभियंता ने सभी मुख्य अभियंताओं, कार्यकारी अभियंताओं और सहायक कार्यकारी अभियंताओं को संबोधित पत्र के माध्यम से 20 वरिष्ठतम सहायक अभियंताओं की सूची मांगी है जो पिछले तीन वर्षों के लिए फॉर्म-II बी में अपनी विश्वसनीय रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। सहायक कार्यकारी अभियंता के पद पर अगली उच्च पदोन्नति के लिए उनके मामलों पर विचार करने के उद्देश्य से जानकारी की आवश्यकता थी। इस मामले को विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष रखा जाना था। उपरोक्त सूची में 20 सहायक अभियंता (मैकेनिकल) थे। डिग्री धारकों की सूची से, अपीलार्थी का नाम क्र. सं. में उल्लिखित किया गया था। नं. 18. डिप्लोमा धारकों की सूची से, क्र. सं. में उल्लिखित उम्मीदवार। नंबर 4 से 7 को एस. एल. में दिखाया गया था। नंबर 2 से 4 और 20, क्रमशः।

7. यह भी तर्क दिया गया कि वर्ष 2004 में, निजी-प्रत्यर्थियों के नेतृत्व में एक रिट याचिका 6 दायर की गई थी जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा उनकी श्रेणी के लिए आरक्षित कोटे में पदोन्नति के लिए उनके मामलों पर विचार करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। इस मामले पर मुख्य अभियंता द्वारा विचार किया गया और 14.03.2005 दिनांकित आदेश के माध्यम से इसका निपटारा किया गया। अभ्यावेदनों पर विचार करते हुए और संबंधित नियमों का उल्लेख करते हुए, मुख्य अभियंता ने निर्देश दिया कि के. सुब्रमण्यन, के. एस. बदरूद्दीन, M.K.Raghavan, K.Sureshan, C.Satheesan और के. के. चंद्राबाबू को 01.08.1993 से प्रभावी होने के साथ सहायक अभियंता के रूप में पदोन्नति दी जाए। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया था कि उन्हें पदोन्नति की तारीख को फिर से सौंपने की तारीख के कारण कोई बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा, हालांकि वे वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे।

8. यह आगे तर्क दिया गया कि निजी उत्तरदाताओं को पता था कि उनके नेतृत्व में उपरोक्त रिट याचिका में पारित आदेश के साथ, अपीलार्थी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसलिए, उन्होंने उसे एक पक्ष के रूप में शामिल किया था, लेकिन

6 2004 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 37212-(ई) (एम. के. राघवन, सहायक अभियंता III बनाम। केरल राज्य) 21.12.2004 पर निर्णय लिया।

149

सी. अनिल चंद्रन बनाम एम. के. राघवन और अन्य [राजेश बिंदल, जे.] 150

तथ्य यह है कि उन्हें कभी भी रिट याचिका का कोई नोटिस नहीं दिया गया था। पिछली तारीख से निजी-प्रत्यर्थियों की पदोन्नति की तारीख को फिर से निर्धारित करने से पहले, जिसने अपीलार्थी की पदोन्नति की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था, उसे मुख्य अभियंता द्वारा सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था।

9. जब अपीलार्थी को दिनांक 1 दिनांकित उपरोक्त आदेश के पारित होने के बारे में पता चला, तो उसने उपरोक्त आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका 6 का नेतृत्व किया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को यह कहते हुए अनुज्ञात कर लिया कि सहायक अभियंता की वरिष्ठता सूची, जैसा कि 22.11.2001 पर प्रसारित की गई थी, शून्य वरिष्ठता सूची थी, जिसे कभी भी निजी-उत्तरदाताओं 1 से 4, 7 और 8 द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी। अपीलार्थी के पूर्वाग्रह के कारण उसे बिना उसे सूचित किए फिर से नहीं खोला जा सकता था। इसलिए, इसे अलग कर दिया गया और अपीलार्थी को वरिष्ठता फिर से निर्धारित करने के लिए एक निर्देश जारी किया गया।

10. विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा पारित उपरोक्त आदेश से व्यथित, उत्तरदाता संख्या 1 से 4 ने रिट अपील को प्राथमिकता दी। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने यह अभिनिर्धारित करते हुए इसकी अनुज्ञात थी कि निजी उत्तरदाताओं की वर्ष 1995 में अलग-अलग तिथियों से 01.08.1993 तक पदोन्नति की एंटी-डेटिंग के साथ, अपीलार्थी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को खंड पीठ द्वारा रद्द कर दिया गया

था। मुख्य अभियंता के दिनांकित 14.03.2005 के आदेश को बहाल कर दिया गया। यह उपरोक्त आदेश है जो वर्तमान अपील में आक्षेपित है।

11. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा वर्णित उपरोक्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स में, तर्क यह है कि निजी उत्तरदाताओं ने कभी भी सहायक इंजीनियरों की वरिष्ठता सूची पर कोई आपत्ति नहीं जताई, जैसा कि 1996-1997 के बीच 2-3 बार प्रसारित किया गया था। जब शून्य वरिष्ठता सूची 22.11.2001 पर प्रसारित की गई थी, तब भी उसे उचित समय के भीतर चुनौती नहीं दी गई थी। इस मुद्दे को तीन साल से अधिक समय बाद उठाने की मांग की गई थी। वह भी शून्य वरिष्ठता सूची को चुनौती देकर, जब सहायक अभियंता से कार्यकारी अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए योग्य उम्मीदवारों के सेवा अभिलेख मांगे गए थे।

12. आगे का तर्क यह था कि निजी उत्तरदाताओं को पता था कि उनकी पदोन्नति की तारीख में बदलाव के साथ, अपीलार्थी को आरोपित किए जाने की संभावना थी, इसलिए, उन्होंने शुरू में दायर रिट याचिका 6 में उसे प्रतिवादी के रूप में शामिल किया था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने कोई अवसर नहीं दिया

/

[2023] 14 एस सी आर।

अपना पक्ष रखने के लिए अपीलार्थी। उच्च न्यायालय द्वारा निजी उत्तरदाताओं के प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए एक निर्देश जारी किया गया था। यहां तक कि जिस मुख्य अभियंता को निर्देश दिया गया था, वह भी इस तरह के किसी भी प्रतिनिधित्व से निपटने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं था। विद्वान वकील ने केरल राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 1958 के नियम 27-बी का उल्लेख करते हुए कहा कि इस तरह का प्रतिनिधित्व केवल सरकार को किया जा सकता है न कि मुख्य अभियंता को। इसके अलावा, मुख्य अभियंता ने दिनांक 14.03.2005 का आदेश पारित करने से पहले अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया था। निजी उत्तरदाताओं की ओवरसियर ग्रेड-I से सहायक अभियंता के रूप में पदोन्नति की तारीख में परिवर्तन ने अपीलार्थी की पदोन्नति की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि उच्च न्यायालय का निर्देश केवल निजी उत्तरदाताओं के प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए था और उन्हें कोई राहत देने के लिए नहीं था। यदि दावे में देरी हुई होती, तो उसे खारिज किया जा सकता था। वर्तमान में केवल सी. सतीशन-प्रतिवादी नं.3 सेवा में है। अपीलार्थी सहित अन्य सभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। विनोद प्रसाद मामले में इस न्यायालय के फैसले पर रिलायंस को रखा गया था।

रतुरी और ओआरएस बनाम। भारत संघ और अन्य, **2021** आई. एन. एस. सी. **157**.

13. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित आदेश, जिसे अपीलार्थी द्वारा आक्षेपित किया गया है, इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप का आह्वान नहीं करता है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य ने केवल निजी

प्रतिवादियों के नेतृत्व में रिट याचिका 6 एफ. आई. में उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश का पालन किया था। चूंकि निजी उत्तरदाताओं को पर्यवेक्षक ग्रेड-I से सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति देने के लिए कोटा की गणना में त्रुटि थी, इसलिए उक्त त्रुटि को ठीक कर दिया गया। अपीलार्थी किसी भी तरह से इस कारण से पर्याप्त नहीं था कि सहायक कार्यकारी अभियंता के पद पर बाद में पदोन्नति के लिए, इंजीनियरिंग स्नातक और डिप्लोमा धारकों के लिए अलग-अलग कोटा थे।

14. अपीलार्थी के इस तर्क के संदर्भ में कि निजी उत्तरदाताओं ने वरिष्ठता सूची में उनकी नियुक्ति के संबंध में कोई आपत्ति नहीं जताई थी, यह प्रस्तुत किया गया था कि उन्होंने सहायक अभियंता के रूप में अपनी पदोन्नति की तारीख को फिर से निर्धारित करने का अनुरोध करते हुए कई अभ्यावेदन किए थे। चूंकि उनका दावा सराहनीय पाया गया था, मुख्य अभियंता ने केवल त्रुटि को ठीक किया था। उन्होंने आर. एम. मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया।

रामूअल बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य। **(1989) 1 एससीसी 285।**

151

सी. अनिल चंद्रन बनाम एम. के. राघवन और अन्य [राजेश बिंदल, जे.] 152

15. प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील नं। 13 प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी को 1989 में अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किए जाने के बाद गलत लाभ प्रदान किया गया था। तीन साल बाद, उन्हें सहायक अभियंता के रूप में नियुक्त करने का निर्देश दिया गया जो पर्यवेक्षक ग्रेड-III से एक पदोन्नति पद था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई आरोप नहीं है कि प्रत्यर्थी नहीं। 13 वरिष्ठता सूची के खिलाफ किसी भी प्रतिनिधित्व का नेतृत्व नहीं किया था। वास्तव में, उन्होंने कई अभ्यावेदनों का नेतृत्व किया था जिन पर उचित विचार नहीं किया गया था। यही कारण है कि एक रिट याचिका का नेतृत्व करना पड़ा। उन्होंने आई. डी. 1 दिनांकित एक ऐसे अभ्यावेदन का उल्लेख किया और उच्च न्यायालय के समक्ष अपने जवाबी हलफनामे में राज्य द्वारा की गई स्वीकृति का भी उल्लेख किया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी को पदोन्नति का अनुदान नं। 13 पिछली तारीख से अन्य निजी उत्तरदाताओं के साथ त्रुटि के सुधार के अलावा और कुछ नहीं था। सहायक कार्यकारी अभियंता के पद पर अगली पदोन्नति नहीं होने वाली थी। उन्होंने आर. एम. रामूअल के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा किया कि पदोन्नति पिछली तारीख से दी जा सकती है और वरिष्ठता सूची को 11 साल बाद भी चुनौती दी जा सकती है।

16. पक्षों की ओर से विद्वानों की सलाह सुनी और संबंधित संदर्भित अभिलेख का अध्ययन किया।

17. यह तथ्य कि वर्तमान में केवल प्रतिवादी संख्या 3 सेवा में है और अन्य सभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, सुनवाई के समय पक्षों के विद्वान वकील द्वारा विवादित नहीं था।

18. हमारे विचार में, यदि किसी वरिष्ठता सूची को चुनौती देने के संबंध में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर आक्षेपित आदेश की जांच की जाती है, तो यह कानूनी रूप से पोषणीय नहीं हो सकता है। आर. एम. रामूल के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय का निर्णय लागू नहीं होगा क्योंकि यह अपने स्वयं के तथ्यों पर एक मामला था जिसमें इस न्यायालय ने पाया कि वरिष्ठता सूची 1971 में तैयार की गई थी, लेकिन बाद में कुछ कर्मचारियों द्वारा किए गए अभ्यावेदन की स्वीकृति पर, इसे बदल दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी के पक्ष में कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ और उस तारीख के बाद से कोई अनुचित देरी नहीं हुई।

19. हाथ में मामले में, वरिष्ठता सूची को निजी उत्तरदाताओं द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी। उन्होंने केवल सहायक अभियंता के रूप में अपनी पदोन्नति की तारीखों में सुधार के लिए अभ्यावेदन दिया, जिसे राज्य द्वारा 14.03.2005 पर औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था।

/

[2023] 14 एस सी आर।

20. यद्यपि, अन्यथा भी, हम यह नहीं मानते कि वर्तमान अपील में हस्तक्षेप के लिए कोई मामला इस कारण से नहीं बनाया गया है कि अपीलार्थी यह प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं है कि सहायक अभियंता के पद से सहायक कार्यकारी अभियंता के पद पर पदोन्नति के उद्देश्य से, उसे निजी उत्तरदाताओं की पदोन्नति की तारीख पूर्व-दिनांकित करके निष्कासित किए जाने की संभावना थी क्योंकि स्नातक अभियंताओं और डिप्लोमा धारकों की श्रेणियों के लिए अगले उच्च पद पर पदोन्नति के लिए अलग-अलग कोटा निर्धारित किया गया था। 2010 के नियमों को अपीलार्थी द्वारा 2017 के आई. ए. संख्या 02 के साथ रिकॉर्ड में रखा गया है, जिसके संदर्भ में डिग्री धारकों और डिप्लोमा धारकों के लिए 8 के अनुपात में अलग-अलग कोटा निर्धारित किया गया है: 2. अपीलार्थी निर्विवाद रूप से ग्रेजुएट इंजीनियर की श्रेणी में आता है, जबकि निजी उत्तरदाता डिप्लोमा धारकों की श्रेणी में आते हैं। दोनों अलग-अलग धाराएँ हैं जिनमें अलग-अलग कोटा हैं।

21. तदनुसार, पक्षकारों को अपना खर्च वहन करने के लिए छोड़ते हुए अपील को निरर्थक बताते हुए खारिज कर दिया जाता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

याचिका खारिज कर दी गई।

अंकित ज्ञान